

प्रेषक,

ओम प्रकाश
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2009

विषय- वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विभिन्न बचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या: 517/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009, शासनादेश संख्या: 216/XII/2009/ 82(05)/2009 दिनांक 06-4-2009, शासनादेश संख्या 268/XII/2009/82(05) दिनांक 03 जून 2009 एवं शासनादेश संख्या 353/XII/2009/82(05) दिनांक 06 जुलाई 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की बचनबद्ध मदों यथा- वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक मदों हेतु संलग्नक में उल्लिखित विभिन्न बचनबद्ध की मानक मदों में (1 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लिए लेखानुदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) प्राविधानित धनराशि कमशः रु0 9127 एवं रु0 18374 हजार, इस प्रकार कुल रु0 27501 हजार (रु0 दो करोड़ पच्चीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उपरोक्तानुसार निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि में 1 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक के लिए लेखानुदान की धनराशि भी सम्मिलित है, जो पूर्व में शासनादेश संख्या: 216/XII/2009/ 82(05)/2009 दिनांक 06-4-2009, शासनादेश संख्या 268/XII/2009/82(05) दिनांक 03 जून 2009 एवं शासनादेश संख्या 353/XII/2009/82(05) दिनांक 06 जुलाई 2009 के द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी है। अतः पूर्व में शासनादेश संख्या: 216/XII/2009/ 82(05)/2009 दिनांक 06-4-2009 शासनादेश संख्या 268/XII/2009/82(05) दिनांक 03 जून 2009 एवं शासनादेश संख्या 353/XII/2009/82(05) दिनांक 06 जुलाई 2009 के द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का समायोजित करते हुए अवमुक्त की जा रही, धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

2. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अविलम्ब कर धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों/शीर्षकों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने एवं निर्वतन पर रखने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
4. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो आय-व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जाय।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम० 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।
7. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी बी०एम०-17 पर आवंटन संबंधी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण- वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे। अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं दिया जायेगा। जिसके लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे।
8. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/ व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनोदशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
9. प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण- वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. विभाग में जहाँ केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होते ही एक प्रॉक्योरमेन्ट प्लान बना लेंगे। इसी प्रकार पूंजीगत कार्यों का भी एक एक्सन प्लान तैयार कर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त/ नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
11. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
12. निर्माण कार्य हेतु पूरे वर्ष की फेजिंग करते हुए लक्ष्य के अनुसार मासिक रूप वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय।

13. जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, में विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय ताकि इन के अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो।
 14. भित्तव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 15. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2010 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस संबंध होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अधीन संलग्न में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष की बचनबद्ध मदों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 515/XXVII (1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोपरि

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या: 488 (1)/XII/09 82(05)09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी-1, /105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड, माजरा, देहरादून।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
- 6- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(आर0पी0फुलोरिया)
संयुक्त सचिव